

कोरोनावायरस से पहले भूख हमें मार देगी : 39वाँ न्यूजलेटर (2020)।



बासंजव चोईजिलजाव (मंगोलिया), वादा, 2018।

प्यारे दोस्तों,

ट्राईकॉन्टिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान की ओर से अभिवादन।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अप्रैल 2020 में महामारी घोषित करने के एक महीने बाद संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफ़पी) ने चेतावनी जारी की थी कि 'यदि त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है' तो साल 2020 के अंत तक कोविड-19 के कारण दुनिया भर में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ग्लोबल नेटवर्क

अगोस्ट फूड क्राइसिस –जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफ़एओ) और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं– की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण खाद्य असुरक्षा साल 2017 के बाद से अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच जाएगी।

इनमें से कोई भी रिपोर्ट अखबारों की सुर्खियाँ नहीं बनीं। और न ही इस बात पर ही ध्यान दिया गया कि यह संकट खाद्य उत्पादन का संकट नहीं –क्योंकि दुनिया की पूरी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन तो होता ही है– बल्कि सामाजिक असमानता का संकट है। भूख की महामारी के इस संकट की ओर हर देश का ध्यान जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन, वियतनाम, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे कुछ देशों को छोड़कर (एफ़एओ की मई में दी गई चेतावनी के अनुसार) अकाल जैसी परिस्थितियों को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर देशों ने बड़े पैमाने पर भोजन कार्यक्रम चलाने की दिशा में बहुत कम काम किया है।

महामारी के छह महीने के बाद भी, भूख का सवाल एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सितंबर में, ग्लोबल नेटवर्क अगोस्ट फूड क्राइसिस ने इस गहराते संकट पर एक नयी रिपोर्ट जारी की है। एफ़एओ के महानिदेशक कू डोंग्यू ने दुनिया के कई हिस्सों में, और विशेष रूप से बुर्किना फ़ासो, दक्षिण सूडान और यमन में ‘भयावह अकाल’ पड़ने की चेतावनी दी है। अनुमान यह है कि दुनिया के हर दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भूख से जूझ रहा है। जबकि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए।



शाइमा अल-तमीमी (यमन), काफ़ी नज़दीक, पर फिर भी बहुत दूर, 2019।

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात के (पश्चिमी देशों व हथियार निर्माताओं द्वारा समर्थित) युद्ध का सामना कर रहा यमन, अकाल और टिड्डियों के साथ-साथ अब महामारी से भी लड़ रहा है। कू के द्वारा दी गई चेतावनी के दो दिन बाद, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन पर चल रहे युद्ध को समाप्त करने की गुहार लगाई। गुटेरेस ने कहा कि युद्ध ने देश की स्वास्थ्य सुविधाएँ बरबाद कर दी हैं। यमन कोविड-19 के लगभग 10 लाख मामलों से निपटने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि युद्ध ने 'करोड़ों यमन निवासियों का जीवन तबाह कर दिया है।'

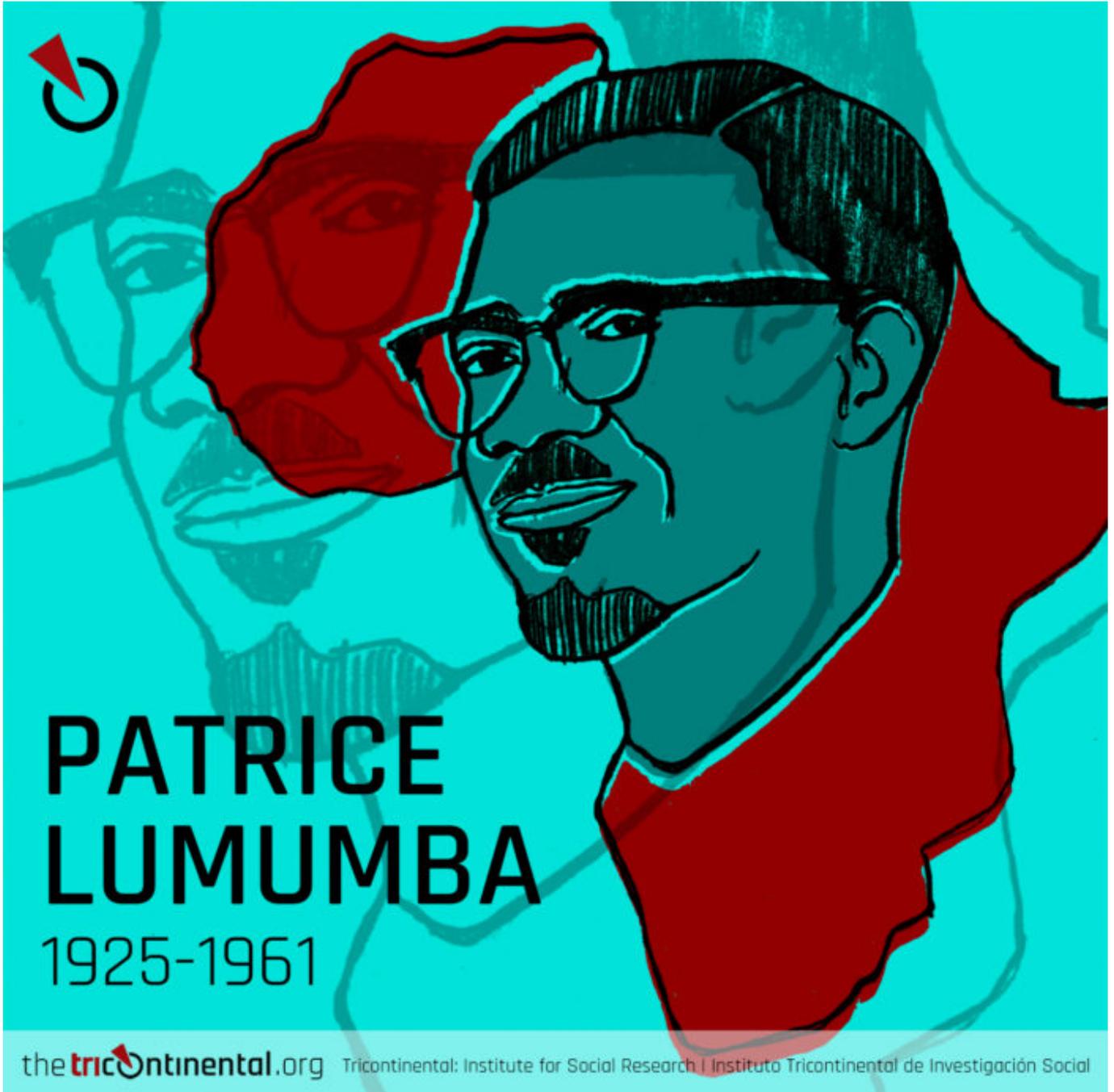
यह समझना महत्वपूर्ण है कि 2015 में सऊदी-अमाराती युद्ध शुरू होने से पहले यमन की जनसंख्या केवल 2.8 करोड़ थी। इसका मतलब है कि इस युद्ध ने यमन की लगभग पूरी आबादी को तबाह कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक नयी रिपोर्ट से पता चलता है कि कनाडा, फ्रांस, ईरान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियारों की बिक्री के द्वारा इस युद्ध को बरकरार रखा है। यमनी लोगों के खिलाफ जारी इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब और अमारात के साथ-साथ पश्चिम देशों के हथियार डीलरों पर दबाव बनाना इस समय की ज़रूरत है। इस युद्ध ने ही यमन में भुखमरी फैलाई है।



तशिंबवा कांडा-मतुलु (DRC), यूरोप के शेर, 1973।

यमन के खिलाफ चल रहे युद्ध की ही तरह लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो (डीआरसी) में चल रहा युद्ध भी दुनिया के लोगों की आम चेतना से बाहर है। इस युद्ध का कारण है देश में कोबाल्ट, कोल्टन, तांबा, हीरा, सोना, तेल और यूरेनियम जैसे संसाधनों की अथाह मौजूदगी। युद्ध, आर्थिक संकट और भारी बरसात के परिणामस्वरूप दिसंबर 2019 में, देश की 8.4

करोड़ की कुल आबादी में से 2.18 करोड़ लोग भयावह भुखमरी की चपेट में थे; कोविड-19 के उद्भव के बाद इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कौंगो देश के सामाजिक संकेतक दयनीय हैं: 72% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है, और 95% आबादी बिजली के बिना लेकिन कौंगो के संसाधनों का अनुमानित धन 24 ट्रिलियन डॉलर है। इस धन का शायद ही कोई हिस्सा कौंगो की जनता पर खर्च होता है।



30 जून 1960 को प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा ने बेल्जियम से डीआरसी की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा था कि 'कौंगो की स्वतंत्रता पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की मुक्ति की दिशा में एक निर्णायक कदम है' और नयी सरकार 'अपने देश की



परमार (भारत), दंगा, 1965-1975।

अब हम भारत आते हैं। नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी सरकार ने राज्य सभा में तीन कृषि विधेयकों को बिना बहस किए केवल ध्वनि मत से पास करवा लिया है। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और सेवा समझौता विधेयक, और आवश्यक वस्तुएँ (संशोधन) विधेयक: इन विधेयकों के नामों से लगता है कि ये छोटे किसानों के हित में हैं, जबकि ये कृषि के व्यवसायीकरण की नीतियाँ लागू करेंगे। ये तीनों विधेयक संपूर्ण कृषि प्रणाली को 'व्यापारियों'—यानी बड़ी कंपनियों—के हवाले कर देंगे, जो अब मूल्य और मात्रा की शर्तें तय करेंगे। सरकार के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में, बड़े निगम न केवल मनमाने ढंग से काम करेंगे बल्कि पारिवारिक खेती करने वाले किसान इन बड़े निगमों के अनुसार खेती करने को मजबूर हो जाएँगे। इसका खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भारत का छोटे किसान और कृषि श्रमिक और गरीब होता जाएगा।

एक ओर भुखमरी बढ़ रही है तो दूसरी ओर खेती करने वालों पर हमला बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत के किसानों और कृषि श्रमिकों का कहना है कि कोरोनावायरस से पहले भूख उन्हें मार देगी। ब्राजील के किसानों और कृषि श्रमिकों का भी यही कहना है। अपने डोजियर संख्या 27 'पॉप्युलर अग्रेरीयन रेफॉर्म एंड द स्ट्रगल फ़ोर लैंड इन ब्राज़ील' में हमने

दिखाया है कि ब्राज़ील के किसान और कृषि मज़दूर लम्बे समय से ज़मीन के लोकतांत्रिकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। संकारा के बुर्किना फ़ासो की तरह, ब्राज़ील के बहादुर भूमिहीनों [सेम टेरास] की अपनी परियोजना है: कृषि-विषाक्त पदार्थों से संतृप्त ज़मीन पर फिर से फ़सलें उगाना, खाली पड़ी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर वहाँ कृषि-पारिस्थितिक तरीक़े से खेती करना, और 'पूरे देश के लिए एक नये दृष्टिकोण की व्यापक माँग' उठाना।

स्नेह-सहित,

विजय।



I am Tricontinental:

Nontobeko Hlela, researcher. Johannesburg Office.

I am interested in global geopolitics, the state form in Africa, regional integration in Africa and strategies to build socially responsive states in Africa. I manage the planning and monitoring process for the work of the South African office, and work on edits for the dossiers that we have recently published like the *Politics of Blood: Repression in South Africa*. Currently I am editing the *Energy Crisis in South Africa Working Document*, the *Wamba paper*, and working on a booklet on *Jabu Ndlovu* a woman trade unionist who was assassinated in the violence in the dying days of apartheid.

tricontinental

नॉटोबेको हलेला, शोधकर्ता, जोहानेस्बर्ग कार्यालय।

मेरी रूचि के है विषय हैं: वैश्विक भू-राजनीति, एक नेशन स्टेट के रूप में अफ्रीका तथा उसके भीतर का क्षेत्रीय एकीकरण और अफ्रीका में सामाजिक रूप से उत्तरदायी सरकार के निर्माण की रणनीतियां। मैं दक्षिण अफ्रीकी कार्यालय के कामों की योजना और निगरानी प्रक्रिया का प्रबंधन करती हूँ। इसके साथ ही मैं हाल में प्रकाशित डोज़ियर 'खून की राजनीति: दक्षिण अफ्रीका में दमन' व अन्यो के संपादन का काम करती हूँ। आज कल मैं दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट पर एक वर्किंग डॉक्यूमेंट, वम्बा पेपर के संपादन का काम कर रही हूँ और जबु नडलोवु -एक महिला ट्रेड यूनियनिस्ट जिनकी रंगभेद व्यवस्था की चरम हिंसा के दिनों में हत्या कर दी गयी थी- पर एक पुस्तिका लिखने का काम कर रही हूँ।